समाचार

दो साल से लटकी है स्टेशन की फाइल

Jan 01, 05:30 am

Print

ग्रेटर नोएडा, संवाददाता: प्रस्तावित बोड़ाकी रेलवे स्टेशन परियोजना आठ साल बाद भी परवान नहीं चढ़ पाई। रेलवे व प्राधिकरण के बीच सैद्धांतिक सहमति होने के बाद पिछले दो साल से फाइल रेलवे मंत्रालय में लटकी पड़ी है। परियोजना को परवान चढ़ाने की जिम्मेदारी अब दिल्ली मुंबई रेलवे कॉरीडोर (डीएमआईसी) को सौंपी गई है। छह माह से डीएमआईसी रेलवे मंत्रालय से फाइल को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी योजना जहां की तहां अटकी पड़ी है।

पिछले आठ साल से ग्रेटर नोएडा में रेलवे स्टेशन को लेकर बात चल रही थी। लेकिन रेलवे विभाग से सहमति न बन पाने के कारण मामला अधर में लटका हुआ था। रेलवे स्टेशन को लेकर सबसे बड़ी अड़चन वित्तीय खर्च को लेकर थी। दिसंबर 2008 मे प्राधिकरण अधिकारियों ने रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी। जिसमें निर्माण में आने वाले खर्च का मुद्दा उठाया गया था। प्राधिकरण स्टेशन निर्माण में आने वाले खर्च को वहन करने के लिए तैयार हो गया था। इस पर रेलवे मंत्रालय के अधिकारियों ने स्टेशन बनाने पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी। जनवरी 2009 में हुई बोर्ड की बैठक में रेलवे विभाग के सैद्धांतिक सहमति का प्रस्ताव रखा गया। जिस पर बोर्ड ने मंजूरी देते हुए सीईओ को इस पर कोई भी फैसला लेने के लिए अधिकृत किया था। रेलवे मंत्रालय व प्राधिकरण के बीच एमयू भी तैयार हो गया था। प्राधिकरण ने जनवरी 2008 में एमयू पर हस्ताक्षर को रेलवे मंत्रालय को भेज दिया था। रेलवे मंत्रालय आज तक एमयू पर हस्ताक्षर नहीं कर पाया।

किस तरह होना रेलवे स्टेशन का विस्तार

बोड़ाकी रेलवे स्टेशन का विस्तार कर उसका नाम परिवर्तित कर ग्रेटर नोएडा स्टेशन रखा जाएगा। रेलवे स्टेशन के निर्माण पर प्राधिकरण 133 करोड रुपये का खर्च प्रस्तावित किया था। जबकि शाइडिंग का निर्माण रेलवे खुद कराएगा। रेलवे स्टेशन के पास ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण कराया जाएगा। रेलवे स्टेशन व ट्रांसपोर्ट हब के लिए 1200 एकड़ जमीन प्राधिकरण ने अधिसूचित कर ली है। स्टेशन के पास फाइव स्टार होटल, माल का भी निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

प्राधिकरण स्तर से क्या किया गया प्रयास

प्राधिकरण के अधिकारिक सूत्रों का कहना है कि रेलवे मंत्रालय को एमयू पर हस्ताक्षर करने के लिए दर्जन भर पत्र भेजा जा चुका है। हर बार रेलवे मंत्रालय द्वारा अध्ययन करने की बात कही गई। बोड़ाकी रेलवे स्टेशन के पास दिल्ली मुंबई रेलवे कारीडोर का नोडल सेंटर बनाया जाएगा। रेलवे मंत्रालय के बीच समन्वय बनाने की जिम्मेदारी अब डीएमआईसी को दी गई है। डीएमआईसी की तरफ से बीते दिसंबर माह में एक प्रस्ताव बना कर रेलवे मंत्रालय को भेजा गया था। प्रस्ताव में कुछ संशोधन करने की बात कहकर मंत्रालय ने प्रस्ताव को वापस भेज दिया। प्राधिकरण सूत्रों का कहना है कि संशोधन के बाद डीएमआईसी ने प्रस्ताव भेज दिया है। लेकिन अभी रेलवे की तरफ से कोई निर्णय नहीं लिया गया।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति